



सांघ्य दैनिक

4 PM

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork [@Editor_Sanjay](https://twitter.com/Editor_Sanjay) [YouTube @4pm NEWS NETWORK](https://www.youtube.com/@4pm NEWS NETWORK)



एक छोटी सी मोमबती का प्रकाश कितनी दूर तक जाता है, इसी तरह इस बुरी दुनिया में एक अच्छा काम चमचमाता है।

मूल्य
₹ 3/-

-विलियम शेक्सपीयर

जिद...सत्त की

• तर्फः 7 • अंकः 283 • पृष्ठः 8 • लखनऊ, उनिवार, 20 नवम्बर, 2021

स्वच्छता रैंकिंग में 12वें नंबर... | 8 | कृषि कानूनों को वापस लेकर... | 3 | भाजपा चुनाव बाद फिर ले आएगी... | 7 |

शहीद किसानों के मुआवजे पर सियासत तेज, किसान बोले

हमें चाहिए एमएसपी कानून

भाजपा सांसद वरुण गांधी भी एमएसपी कानून के पक्ष में

» विपक्ष ने कहा- न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बने कानून और किसानों पर दर्ज केस लिए जाएं वापस □□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन काले कृषि कानून वापस लेने के बाद अब भाजपा के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है।

राकेश टिकैत सहित देश के किसानों ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने खेत रूप से कहा आंदोलन तभी खत्म करें जब सरकार एमएसपी के साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। वहीं भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी कानून के पक्ष में किसानों का समर्थन किया है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा पीएम मोदी को पत्र लिखा है।

विपक्ष ने आंदोलन में शहीद हुए किसानों को कम से कम एक करोड़ मुआवजा देने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी मोदी के अंहंकार की हार है। अब आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवार को एक-एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा दिया जाए तो ही देश के किसान प्रधानमंत्री को माफ कर पाएं। मायावती ने भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बने और किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं तो ही किसान खुश होंगे।



एक करोड़ का मुआवजा दिया जाए

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने किसानों से जुड़े एमएसपी के मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार से

आदेलन के दैशन जान गंवाने वाले किसानों के लिए 1-1 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा करने की अपील की है। वरुण ने लिखा कि इस आदेलन के दैशन 700 से ज्यादा किसान 'शहीद' हो गए हैं और यह दैशन पहले ही ले लिया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा आदेलन के दैशन शहीद देवे गाए द्वारा किसान मार्फ़ बहनों के परिवारों के प्रति सावना जताने के दैशन, प्रत्येक के लिए एक करोड़ के मुआवजे की घोषणा की जाए।

किसानों के साथ हैं तो टेनी को करें बर्खास्त

कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने लखीमपुर में किसानों को रौदरों की घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पीएम से कहा है कि यदि सच्चे हृदय से किसानों के साथ हैं तो लखीमपुर कांड के आरोपित के पिता केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करें। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के साथ मंच साझा किए जाने का भी जिक्रपत्र में किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील की है कि उनके साथ मंच साझा न करें। प्रियंका गांधी ने पत्र में आगे लिखा कि मैं लखीमपुर कांड के पीड़ित परिवारों से मिली हूं। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ़ न्याय वाहते हैं और टेनी के पद पर बने रहते न्याय संभव नहीं है। वहीं कांग्रेस किसानों के समर्थन में आज पूरे प्रदेश में किसान विजय दिवस मना रही है।



किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए

आम आदपी पार्टी से राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि कृषि कानून वापसी मोदी के अंहंकार की हार है। प्रधानमंत्री मोदी को अब एक और घोषणा करनी चाहिए कि आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को एक-एक करोड़ मुआवजा मिलेगा। साथ ही सरकारी नौकरी और शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तभी किसानों को उचित न्याय मिल पाएगा।

किसान बिल वापस लेना भाजपा का चुनावी स्टंट

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने कहा किसान बिल वापस लेना भाजपा का चुनावी स्टंट है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से क्या किसान वापस जिंदा हो जाएंगे जो आंदोलन में शहीद हुए। उन्होंने कहा भाजपा से ज्यादा देश को किसी ने भ्रमित और धोखे में नहीं रखा। उन्होंने कहा यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है।



पुलिस प्रमुखों को पीएम मोदी दे रहे सुरक्षा का मंत्र

» डीजीपी कॉर्नफ़ेस में शामिल हुए प्रधानमंत्री व शाह □□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क



इससे पहले कल रात लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृहमंत्री

अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने स्वागत किया। पीएम

पुलिसिंग को नहीं होना चाहिए राजनीति का शिकार : शाह

डीजीपी कॉर्नफ़ेस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिसिंग और राजनीति अलग-अलग है। पुलिसिंग को राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने केन्द्र व राज्यों की एजेंसियों में बेहतर तालिमेल पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया को लेकर कहा कि ऐसी पोस्ट जो कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले होते हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए।

मंच साझा कर दिए अजय मिश्र टेनी

डीजीपी कॉर्नफ़ेस में जब अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी ने मंच साझा किया तो विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष ने कहा किसानों को कुछलने वाला मंच पर है। इससे अंदाजा लगाए जिकरी भाजपा किसानों के साथ किस तरह खड़ी है।

किया। मोदी ने राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।



जल्द देश की रक्षा जरूरतों का 90 फीसदी सामान होगा मेड इंडिया : राजनाथ सिंह

» सेना के कमांडरों के साथ बंद कमरे में की बैठक

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। ज्ञासी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह दिन जल्द आएगा जब देश की रक्षा जरूरतों के 90 फीसदी उपकरण भारत में बनेंगे। राजनाथ सिंह ने कल ज्ञासी में पीएम मोदी के साथ यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ज्ञासी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की रक्षा उपकरण इकाई एवं अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का शिलान्यास किया।

उधर सेना के शीर्ष कमांडरों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लद्दाख में गतिरोध वाले स्थान पर भारत द्वारा दावा की गई लाइनों से चीन के पीछे हटने से बार-बार इनकार करने की सूचना दी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख के रेजांग ला में एक पुनर्निर्मित बाँवर मैमोरियल का उद्घाटन किया, जो समुद्र तल से 18000 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। इसी जगह मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमांयू रेजिमेंट की कंपनी के जवानों ने 1962 में चीनी सैनिकों का बहाहुरी से मुकाबला किया था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के उत्तरी कमान के कमांडरों के साथ बंद कमरे में बैठक की। कमांडरों ने राजनाथ सिंह को चीन द्वारा देपसांग मैदान और हॉट स्प्रिंग्स के कब्जे वाले क्षेत्रों से पीछे हटने से इनकार करने की सूचना दी। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया



कि ये बैठक एक घंटे से अधिक समय तक चली। इस दौरान कमांडरों ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और रक्षा मंत्री को भारत द्वारा दावा किए गए लाइनों के भीतर गतिरोध वाले स्थानों पर बढ़े पैमाने पर चीनी जमावड़े के बारे में अवगत कराया। बैठक के दौरान कमांडरों ने बताया कि कैसे चीनी सैनिकों ने एयरबेस और

25 नवंबर को सीतापुर जाएंगे राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 नवंबर को लखनऊ आएंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 नवंबर को गोखला पुर और 23 को कानपुर थेट्रो के बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में शामिल होकर उनका हैसला बढ़ाएंगे। इसी तरह अमित शह को यह जिम्मा सौंपे जाने के विषेश मायाने हैं। वह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही जापा-देश के प्रगारी भी रह चुके हैं। यूपी अध्यक्षों से सीधे लेखक होने की याजनीकृत परियों उन्होंने ही 2014 के लोकसभा चुनाव में शुरू की थी। इन दो क्षेत्रों में कुल 136 विधान सभा सीटें हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन की जगह से परियों को यूनौटीर्ण माना जा रहा है, इसलिए कुशल टण्टिकार के तौर पर अमित शह यहां के बूथ अध्यक्षों को रण-कौशल दिखाएंगे। हालांकि उन्होंने अपने कार्यक्रम तय नहीं हो सके हैं। इसी तरह कार्यालय और अवधि के लिए राजनाथ सिंह को काफी प्रभावी माना जा रहा है। वह यूपी मूल निवासी कार्यों के चांदीली के हैं और उनका लोकसभा थेट्रो अवधि में है। दोनों ही क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ के साथ निलंबन स्तर तक कार्यकर्ताओं से जुड़ा है। अनुग्रही राजनाथ 25 नवंबर को अवधि का सम्मेलन सीतापुर में करेंगे, जहां कार्यालय के लिए जौनपुर को चुना है, जहां वह 27 को सम्मेलन करेंगे।

सैन्य शिविरों का निर्माण करके गतिरोध वाले स्थानों पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। वहाँ मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि राजनाथ सिंह ने कमांडरों से कहा कि भारत इस मामले को फिर से चीनी सेना के साथ अगली सैन्य और राजनयिक वार्ता के दौरान कमांडरों ने

चुनावों में हार दिखने लगी तो वापस लिया कानून : प्रियंका

» कांग्रेस महासचिव ने पीएम मोदी पर कसा तंज

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने पर हमला बोला है। उन्होंने मोदी के इस फैसले पर कई सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार के मरियों ने किसानों को क्या-क्या नहीं कहा? आंदोलनजीवी, गुड़े, आतंकवादी, देशद्रोही- इन सबका किसान बुलाया? जब यह सब कहा जा रहा था, तो पीएम चुप रहो थे? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने खुद आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया है।



सब कहा जा रहा था, तो पीएम चुप रहो थे? प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने खुद आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया है।

प्रियंका गांधी ने ट्रिकॉट कर पीएम मोदी के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के बाद 600 से अधिक किसानों की शहादत हो गई और 350 से अधिक दिनों तक जब किसान संघर्ष कर रहे थे, तब पीएम मोदी को कोई परवाह नहीं थी। साथ ही प्रियंका गांधी ने लखीमपुर में पीएम मोदी की चुप्पी पर भी प्रश्न उठाया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी कृषि कानून वापस लेने के बाद से लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर लाठियां बरसायीं गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब जब चुनाव में हार दिखने लगी, तो मोदीजी को अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह देश किसानों ने बनाया है, यह देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। उन्होंने सरकार का दोहरा चरित्र बताते हुए कहा कि आपकी नीयत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है। किसान की सदैव जय होगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाने का रास्ता साफ

» नियमावली में संशोधन, दो साल बढ़ाई गई अधिकतम आयु सीमा

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत एवं स्थानीय निकाय मनोज कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के लिए नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है।

कार्यकाल बढ़ने से मनोज विधानसभा चुनाव बाद 2022 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव भी करा सकेंगे। सरकार ने 1982 बीच के आईएस अधिकारी मनोज कुमार को जनवरी 2018 में प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया था। वे 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद फरवरी 2014 में प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।

मौजूदा नियमावली के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष एवं अधिकतम 68 वर्ष है। इस तरह उनका कार्यकाल फरवरी

मनमाफिक आयुक्त के लिए अब तक कई बार नियमों में बदलाव

राज्य सरकारें पंचायत व नगरीय निकाय के चुनावों में मनमाफिक आयुक्त बनाए रखना चाहती हैं। इसके लिए अब तक तीन बार आयुक्तों का कार्यकाल घटाया-बढ़ाया जा चुका है। शासन ने 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायतराज और स्थानीय निकाय, नियुक्ति और सेवा की शर्त) नियमावली बनाई थी। पहले आयुक्त का कार्यकाल 7 वर्ष की अवधि व अधिकतम 67 वर्ष आयुसीमा थी। इसके बाद इसे घटाकर पांच वर्ष व अधिकतम 67 वर्ष आयुसीमा 65 वर्ष कर दी गई। वर्ष 2014 में संशोधन के जरिए आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष व अधिकतम 68 वर्ष किया गया। अब नए संशोधन में अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गई है।

2022 में खत्म हो रहा है। फरवरी में ही विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में तब नए आयुक्त की नियुक्ति संभव नहीं होगी। दूसरा, नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 से पूर्व नगरीय निकाय की मतदाता सूची भी तैयार की जानी है। यह कार्यवाही समय से हो लिहाजा मौजूदा आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया। पंचायतीराज विभाग ने इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायतराज और स्थानीय निकाय) के लिए बनाए रखे तक अपने पद पर बने रह सकेंगे।

नियुक्ति और सेवा की शर्तों नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव किया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 68 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम आयुसीमा 70 वर्ष करने का प्रस्ताव किया था, जिसे कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन में मांजूरी दे दी है। नियमावली में संशोधन से मनोज का कार्यकाल दो वर्ष और बढ़ जाएगा। अब वे जनवरी 2024 में 70 वर्ष की उम्र पूरी होने तक अपने पद पर बने रह सकेंगे।

अन्य कार्यकाल दो वर्ष एवं अधिकतम 68 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम 70 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 70 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम 72 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 72 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम 74 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 74 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम 76 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 76 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम 78 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 78 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम 80 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 80 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम 82 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 82 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम 84 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 84 वर्ष के स्थान पर छह वर्ष व अधिकतम 86 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके तहत आयुक्त का कार्यकाल छह वर्ष व अधिकतम 86 वर्ष के स्थान

2022 के चुनाव से पहले भाजपा का मास्टर स्ट्रोक

कृषि कानूनों को वापस लेकर भाजपा ने विपक्ष से छीना एक और मुद्दा

- » किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव आंदोलन करने वाले दल और नेता हुए बेरोजगार
- » पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के बाद भाजपा का एक और मास्टर स्ट्रोक

दिव्यभान श्रीवास्तव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल तथा डीजल के दाम कम करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से तीन कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा से भाजपा विपक्ष के हमले की धार को कुंद करने के प्रयास में हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ देश के साथ उत्तर प्रदेश में विपक्ष भाजपा की सरकार पर बोहूद मुख्यर था। साथ ही विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में इस मुद्दे को भुआने की बड़ी योजना भी बना ली थी।

इसी बीच किसी को भी जरा सी खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संदेश में इतनी बड़ी घोषणा कर देंगे। इससे पहले भी केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार ने पेट्रोल तथा डीजल के दाम में भारी कमी करके लोगों को बड़ी महंगाई से थोड़ी राहत देने का प्रयास किया था। साथ ही इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर भी सरकार ने महंगाई को लेकर विपक्ष के हमले को ठंडा किया था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पीएम नरेन्द्र मोदी के तीन कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद कहा कि भाजपा किसानों के लिए सब कुछ करने को तैयार थी है और रहेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा विरोधी विपक्षी दलों और नेताओं को जो किसानों को गुमराह कर रहे थे को अब बेरोजगार कर दिया है। किसानों के नाम पर राजनीतिक दुकान चलाने वालों को नींद नहीं आएगी। आगामी चुनाव में विपक्ष की सारी साजिशें फेल होंगी। भाजपा 300 का आंकड़ा पार करेगी। यही नहीं, अब विपक्ष को मुद्दा ढूँढ़ा पड़ेगा। क्योंकि भाजपा सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। 2017 की तरह इस चुनाव में भी किसान भाजपा के साथ खड़ा है।

किसानों के हौसलों को क्रूपलने में कामयाब नहीं हो पाई सरकार



“**तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अद्वितीय कराया हूं।** किसान आंदोलन के नाम पर चुनाव अंदेलन करने वाले और नेता तो को बेरोजगार हो गए हैं। इनकी कोई भी साजिश अब सफल नहीं होगी कगल खिला है और खिला ही रहेगा।



“**पिछले एक साल से देश का किसान प्रायुक्ति मांगों के साथ इकट्ठों पर बैठा है।** आज प्रधानमंत्री द्वारा इसने से केवल एक मांगों पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कह पाए। एकास्थी की गार्डी, किसानों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसी के ऊपर प्रधानमंत्री का कुछ न बोलन नियाशानक है। लगता है कि किसानों को अपना संघर्ष अभी जारी रखना पड़ेगा। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि है।



“**तीनों कृषि कानूनों की वापसी किसानों की जीत है।** अंदेली की लागत है। प्रधानमंत्री को देखी से अब आई, देख से आए लेकिन दुर्लक्ष आए। यह उन सभी किसानों, संगठनों व जगनानास की जीत है, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया।

सतीश श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी

निर्णय, प्रदेश अध्यक्ष उपायुक्त

बर्बाद होने से बच गए देश के अन्नदाता

कृषि कानून वापस लेने के ऐलान से किसानों में दैपनिकी जैसी खुशी है। यह किसानों की जीत है। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ललित त्यानी ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेना किसानों की एकता की जीत है। इस फैसले का सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश जाएगा। यदि तीनों कृषि कानून लागू हो जाए तो किसानों की बर्बादी होती रहिएगी अब ऐसी बर्बादी होने से बच जाएगी। अन्नदाता की जीत है।



आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा

काहेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवधीनी ने कहा यदि यूपी, पंजाब सहित अन्य याज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं होते तो यह कृषि कानून वापस नहीं होते गाल थे। जिस तरह से किसानों ने एक साल तक संघर्ष किया है उसी का परिणाम है कि सरकार को झुकना पड़ा। देख से ही सही लेकिन सरकार के समझ में आ गया कि किसानों को दबाया नहीं जा सकता इसलिए तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। यह जीत अन्नदाता की जीत है।



किसानों की एकता के आगे झुकी तानाशाही सरकार

मुजफ्फरनगर के छापर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने कहा कि यह किसान एकता की जीत और तानाशाही सरकार की हार है। संसद में भी सरकार कानूनों को रद्द करे। लगभग 700 किसानों की शहदत पर ही कृषि कानूनों की वापसी हुई है। सरकार बेरोजगार ही कृषि कानूनों को किसानों पर थोपना चाहती थी। परंतु किसानों की एकता के सामने सरकार को झुकना ही पड़ा। 22 सितंबर 2020 से किसान गर्मी, सर्दी व बरसात के मौसम में भी दिल्ली बांडर पर डटे हुए थे। जिसमें लगभग 600 किसान शहीद हो गए। उन्होंने सरकार से शहीद किसानों को सम्मान देते हुए उनके परिवार को आर्थिक सहायता व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी की मांग की है और शहीद किसानों की दिल्ली बांडर पर ही समाधि स्थल बनाने की मांग की है।

वेस्ट यूपी में जमकर आतिथबाजी, बजे ढोल नगाड़े



पीएम मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी घोषणा करते तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। यह एक बड़ा ऐलान है जिसके वेस्ट यूपी सहित देशभर में किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब तीनों कानूनों की वापसी के बाद किसान भार्डी बोले कि वह सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, यह घोषणा सरकार को पहले ही कर देनी चाहिए थी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने पर बुलंदशहर, मेरठ, बरेली, बागपत, मथुरा सहित पूरे प्रदेश में पटाखे छोड़कर किसानों ने खुशी का इजहार किया। साथ ही कई स्थानों पर ढोल नगाड़े भी बजाए गए।

हक के लिए संघर्ष होता रहेगा, अभी एमएसपी पर जारी रहेगी लड़ाई

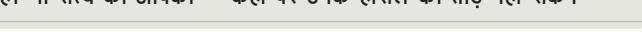
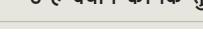
केंद्र सरकार को अभी एमएसपी पर विद्यार करना चाहिए। ताकि किसानों को राहत मिल सके और फसलों का वाजिब दाम मिल सके। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एक साल आंदोलन को होने वाला था। आंदोलन में काफी किसानों की शहदत भी हुई। किसान मान सम्मान और हक के लिए संघर्ष करते रहे। संसद में कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद ही उनका आंदोलन समाप्त होगा। चुनावी मौसम में सरकार ने तीनों कृषि कानूनों की घोषणा की है। राकेश टिकैत ने दो टूक कहा कि एमएसपी कानून लागू होने की मांग भी जारी रहेगी।



ज्ञानेवाले किसानों के हौसले को सरकार कुचलने में कामयाब नहीं हो पाई। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला पर आप और आपकी प्रदेश सरकार ने हर सभव कोशिश की उन्हें बचाने की किन्तु वहां भी सत्य को आपकी सत्ता की ताकत रोद नहीं पायी। आरएलडी नेता अनुपम मिश्रा ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा, प्रधानमंत्री ने खुद किसानों को आंदोलनजीवी कहा पर उनके हौसले को तोड़ नहीं सके।



आरएलडी के राष्ट्रीय संयोजक अनुपम मिश्रा ने कहा सरकार को काले कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। यह किसानों की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा 600 से अधिक किसानों की शहदत और 350 से अधिक दिनों से खुले आसमान के नीचे जाड़ा, गर्मी और बरसात को





Sanjay Sharma

f editor.sanjaysharma

t @Editor_Sanjay

“

पत्रकारों के लिए पाकिस्तान खतरनाक देश है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यह 180 देशों में 145वें स्थान पर है। लेकिन इस हफ्ते पूरे देश में उस वक्त खलबली मध्य गई, जब एक बेहद लोकप्रिय जन ने एक पत्रकार, अखबार के मालिक और संपादक समेत एक मीडिया ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में तलब किया। गिलगित-बाल्टिस्तान के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश राणा मोहम्मद शमीम ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने एक अन्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीएलए (एन) प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को जमानत न दी जाए और उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति न दी जाए।

न्यायमूर्ति शमीम का आरोप है कि साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को फोन कर दोनों की जमानत याचिका खारिज करने के लिए कहा। जाहिर है, साकिब निसार ने इससे इकार किया है कि उन्होंने कभी अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया है। न्यायमूर्ति शमीम ने अपना यह खुलासा एक विस्फोटक शपथपत्र के जरिये पेश किया। मोहम्मद शमीम के आरोपों के पीछे की सच्चाई की जांच के लिए न्यायिक जांच का आदेश देने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिन्हाज ने उत्तर रिपोर्टर, संपादक और द न्यूज और जंग समूह के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के लिए कहा। राणा मोहम्मद शमीम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जिद... सच की

पाक में न्यायपालिका बनाम मीडिया

पत्रकारों के लिए पाकिस्तान खतरनाक देश है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में यह 180 देशों में 145वें स्थान पर है। लेकिन इस हफ्ते पूरे देश में उस वक्त खलबली मध्य गई, जब एक बेहद लोकप्रिय जन ने एक पत्रकार, अखबार के मालिक और संपादक समेत एक मीडिया ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कोर्ट में तलब किया। गिलगित-बाल्टिस्तान के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश राणा मोहम्मद शमीम ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने एक अन्य न्यायाधीश को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीएलए (एन) प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को जमानत न दी जाए और उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति न दी जाए। न्यायमूर्ति शमीम का आरोप है कि साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को फोन कर दोनों की जमानत याचिका खारिज करने के लिए कहा। जाहिर है, साकिब निसार ने इससे इकार किया है कि उन्होंने कभी अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया है। न्यायमूर्ति शमीम ने अपना यह खुलासा एक विस्फोटक शपथपत्र के जरिये पेश किया। मोहम्मद शमीम के आरोपों के पीछे की सच्चाई की जांच के लिए न्यायिक जांच का आदेश देने के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिन्हाज ने उत्तर रिपोर्टर, संपादक और द न्यूज और जंग समूह के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी कर अदालत में पेश होने के लिए कहा। राणा मोहम्मद शमीम को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ही अजीब टिप्पणी की कि अधिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्च न्यायपालिका की अखंडता से ज्यादा नहीं। उनकी यह टिप्पणी असंगत है, क्योंकि मीडिया और न्यायपालिका मुलक के दो संभंह हैं और कोई इसका आकलन नहीं कर सकता कि कौन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका में जनता के विश्वास को भी कम करता है। क्या मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार को भी तलब करेंगे और कारण बताओ नोटिस भेजेंगे, जो इस न्यायिक ड्रामे में मुख्य किरदार हैं? कोई भी मीडिया प्रकाशन से उसकी खबर का स्रोत नहीं पूछ सकता, क्योंकि मोहम्मद शमीम का जो हलफनामा प्रकाशित हुआ था, वह लंदन में एक खुला और सार्वजनिक दस्तावेज है। यदि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के आरोपों के बारे में पूरी जांच करने से परहेज करता है, तो वह जनता का विश्वास भी खो देगा। स्वतंत्र मीडिया द न्यूज इंटरनेशनल और जंग के पूर्ण समर्थन में सामने आया है और यह सबाल उठाया है कि अपने घर को व्यवस्थित करने के बजाय न्यायपालिका द्वारा मीडिया हाउस पर निशाना साधना आखिर कितना उचित है। इस पर जरा गौर करें।

२०१५

(इस लेख पर पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

प्रभु चावल

क्या भारतीय नौकरशाही का कुछ्यात स्टील ढांचा अब ऐल्यूमिनियम में बदल गया है। मोदी सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे विशेषाधिकार को प्रभावहीन कर दिया है और दफ्तरी बाबुओं के चुरू पैंतरों को नाकाम कर रही है। बीते पांच साल से वे नियमित रूप से कार्यालय जा रहे हैं और बैठकों में शामिल हो रहे हैं। सेवानिवृत्त अधिकारियों की मानें, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का ढांचा तेजी से बदल चुका है। अब शीर्ष स्तर पर निर्णय लिये जाते हैं और उन्हें लागू करने के लिए नीचे भेजा जाता है। पहले बेरपवाह अधिकारियों को वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की जानकारी रहती थी, पर अब जब आधी रात को कार्मिक विभाग के वेबसाइट पर नाम घोषित होते हैं, तो उन्हें झटका लगता है। इन दिनों वित्त मंत्री के आगले मुख्य अर्थिक सलाहकार के संभावित नाम को लेकर क्यास लाया जा रहे हैं।

क्या देश की पहली महिला वित्तमंत्री को पहली महिला सलाहकार मिलेंगी? क्या अपने ढंग से फैसले लेनेवाले प्रधानमंत्री मोदी ब्रेंटवुड संस्थाओं से किसी को लायेंगे या किसी भारतीय अर्थशास्त्री को पसंद करेंगे? इस पद के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। सत्ता के गलियों में जो तीन संभावित नाम चर्चित हैं, उनमें शीर्ष पर डॉ पर्सी दुआ का नाम है, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। मोदी सरकार ने 2016 में उन्हें रिजर्व बैंक की शक्तिशाली मीडिया नीति समिति की पहली महिला सलाहकार में चार सालों के लिए नामित किया था। देश में वे शायद पहली भरोसेमंद अर्थशास्त्री हैं। दूसरी प्रतिष्ठित देशी अर्थशास्त्री पूनम गुप्ता हैं, जो अभी नेशनल कार्डिसिल ऑफ अप्लायड

भाजपा चुनाव बाद फिर ले आएगी कृषि कानून: अखिलेश यादव

» आगामी चुनाव में जनता इन्हें माफ नहीं साफ करेगी

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि कानून वापसी को चुनावी दाव बताते हुए कहा है कि इनका दिल साफ नहीं है। चुनाव बाद यह लोग फिर कृषि बिल लेकर आएंगे। केंद्र सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। माफी मांगने वालों को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जनता अब इन्हें माफ करने के बजाए आने वाले वक्त में इन्हें साफ करने का काम करेगी। वोट के लिए कानून वापस ले लिए गए हैं क्योंकि सरकार चुनावों से डरती है।

अखिलेश यादव ने कहा कि इन कानूनों की वापसी अंहकार की हार और किसानों की जीत है। जिस मंत्री ने लखनऊ में किसानों को कुचला उसको भी बर्खास्त किया जाए। अखिलेश ने कहा कि सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के सामने किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। यह लोग सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग कर फिर से आएंगे। सपा मुखिया ने कहा कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो पहले ऐसा फैसला कर लेंगे।



हमारी रथयात्रा में जनसमर्थन से डरकर वापस लिए काले कानून

इससे पहले अपने आधिकारिक टिवटर हैंडल से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा अखिलेश यादव ने कहा कि अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण त काले कानूनों से गरीबी-किसानों को ठगना चाहा। कील लगाई, बाल खींचते कार्बून बनाए, जीप चढ़ाई लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले-कानून वापस ले ही लिए। भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब निलेगा।

मारे गए किसान वया जिंदा हो जाएंगे?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर पटलवार करते हुए निशाना साधा। झांसी पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि किसान बिल वापस लेना भाजपा का चुनावी स्टॉप है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने से वया किसान वापस जिंदा हो जाएंगे जो आदोलन में शहीद हुए। रामगोपाल ने आगे कहा कि भाजपा से जयदा देश को किसी ने भ्रमित और धोखे में नहीं रखा। उन्होंने कहा या यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है।

रक्षामंत्री के प्रतिनिधि की एलडीए और नगर निगम में नहीं हो रही सुनवाई

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि डॉ. राघवेंद्र शुक्ला व दिवाकर त्रिपाठी द्वारा कई बार पत्राचार करने के बाद भी डेढ़ सौ मीटर रोड न तो लखनऊ विकास प्राधिकरण बना रहा है और न निगम। इसके कारण चिनहट तिराहे से हाईकोर्ट की तरफ जाने वाली सर्विस लेने पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सड़क के किनारे अतिक्रमण हावी है। नगर निगम कहता है कि एलडीए बनवाएगा और लखनऊ विकास प्राधिकरण कहता है कि यह क्षेत्र नगर निगम के अंतर्गत आता है। दोनों विभागों की खींचतान में रक्षामंत्री के प्रतिनिधि की सुनवाई अधर में लटकी हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, यह पत्राचार अगस्त 2021 से चल रहा है। इसका खामियाजा यहां रहने वाले सैकड़ों आवंटी भगतने को विवश हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की नूर कुश्ती में लोग जर्जर सड़क पर चलने के लिए मजबूर हैं। यह हाल तब है जब रक्षामंत्री के प्रतिनिधि द्वारा लालिप्रा व नगर निगम को पत्र लिखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों विभागों में काम करवाना कितना मुश्किल है। जब जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करवा पा रहे तो आज जनता यहां कैसे काम करवा पाएगी। बता दें कि अवस्थापना का कई सौ करोड़ रुपये दोनों विभागों के पास मौजूद हैं।

महाराजा बिजली राजकीय कॉलेज में विषयीय परिषद का उद्घाटन

» छात्र/छात्राओं को परिषद के तहत होने वाली गतिविधियों के बारे में दी जानकारी

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क



लखनऊ। आशियाना में महाराजा बिजली राजकीय महाविद्यालय की मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉ. सनोबर हैदर ने बताया कि कॉलेज की प्राचार्य प्रौ. डॉ. सुमन गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन में सत्र 2021-22 हेतु छात्र / छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विषयीय परिषद का उद्घाटन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र/छात्राओं को परिषद के तहत होने वाली गतिविधियों से परिचित कराया गया एवं परिषद में उनकी भूमिका और सहभागिता की उपर्योगिता को बताते हुए उनके आत्मविश्वास और किसी भी कार्य को कर सकने के लिए क्षमता का बोध कराया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक एवं सभी संकाय के छात्र/छात्राओं ने सहभागिता की।

मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉ. सनोबर हैदर ने बताया

कि इस कार्यक्रम की शुरूआत प्राचार्य द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के द्वारा किया गया। छात्र/छात्रा प्रतिनिधि द्वारा प्राचार्य एवं वरिष्ठ प्राध्यापकों का स्वागत पुष्प प्रदान करके किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. दीपि सोनकर ने किया। इस अवसर पर कराई गयी सामान्य ज्ञान (किवज) प्रतियोगिता को डॉ. अजीत कुमार द्वारा ने सम्पन्न कराया, जिसमें 42 छात्र / छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभागिता किया। इसमें एमए समाजशास्त्र के छात्र जितेन्द्र कुमारहा ने प्रथम पुरस्कार, बीकाम तृतीय वर्ष के छात्र कुलदीप कुमार ने द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशान्त कुमार ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।



लखनऊ। लायन्स क्लब लखनऊ अमन बैनर के तले क्लब की अध्यक्षा ममता सिंह ने राजधानी में जलरतमंद बच्चों को रेटर्ट वितरित किए। साथ ही बच्चों को खाना भी खिलाया। राधिका कोचर, सुनीति श्रीवास्तव, ममता पांडेय, सुरेणा रंजन आदि का भी विशेष सहयोग रहा।

हमें किसी का मतांतरण नहीं करना है जीने का तरीका सिखाना है: भागवत

» संघ प्रमुख ने कार्यक्रम में पढ़ाया धर्मपरायणता का पाठ

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क



बिलासपुर। आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने बिना नाम लिए मिशनरियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें किसी का मतांतरण नहीं करवाना है, बल्कि जीने का तरीका सिखाना है। हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है। हमारा पंथ किसी की पूजा पढ़ति, प्रांत और भाषा बदले बिना अच्छा मनुष्य बनाता है। किसी को बदलने की चेष्टा न करें। सबका सम्मान करें।

आरएसएस प्रमुख ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के मदकद्वीप में आयोजित घोष शिविर में कहा कि मेरा सौभाग्य है कि देव दीपावली के अवसर पर मैं हरिहर क्षेत्र में हूं। हम सबमें भावात्मक एकता आनी चाहिए। हमारी आवाज अलग-अलग हो सकती है। रूप अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन, सुर एक होना चाहिए। हम सबका मूल

लखनऊ में धूमधाम से मनी देव दीपावली

» रंगोली बनाकर दिया जय श्री राम का संदेश

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क



लखनऊ। काशी ने इस बार देव दीपावली पर अयोध्या का रिकार्ड तोड़ दिया। अयोध्या में दीपावली पर 12 लाख दीपे जलाए गए थे। जबकि वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर 84 गंगा घाटों पर 15 लाख दीपे जलाए गए। 2 लाख से ज्यादा लोग 84 घाटों पर पहुंचे। पर्यटकों ने गंगा में नीका की सगरी की।

गंगा में छोटे से लेकर बड़े सभी नाव, स्टीमर और क्रूज पर पर्यटकों ने पार्टी की। सैम मानिक शांति और अलकनन्द क्रूज की महंगी सवारी भी पर्यटकों को खूब पसंद आई। सबसे आकर्षित करने वाला दृश्य राज चेत सिंह घाट पर दिखा। यहां लेजर लाइट और साउंड से बाबा विश्वनाथ का तांडव नृत्य व काशी का अध्यात्म दिखाया गया। वहां राजधानी लखनऊ में भी देव

स्थानीय निवासी मौजूद थे। दिवाली पर्व मनाया गया। मां मनपूर्णा मंदिर टिकैतराय एलडीए कॉलोनी के प्रांगढ़ में 1100 दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर नागेंद्र अवस्थी, राजेश मिश्रा(राजन), नोटेश किशोर दीक्षित, प्रियांशु दीक्षित, दीपांशु दीक्षित, अमन अवस्थी, ऋषि दीक्षित, सरोज गुप्ता, शिवनाथ सैनी सहित स्थानीय निवासी मौजूद थे।

गंगा शहरों की श्रेणी में वाराणसी को मिला पहला स्थान स्वच्छता रैंकिंग में 12वें नंबर पर लखनऊ

» इंदौर लगातार 5वीं बार
सबसे स्वच्छ शहर घोषित

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वच्छ शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 प्रदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इंदौर को लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मगर का इंदौर पहले स्थान पर रहा तो राष्ट्रपति कोविंद ने गुजरात के सूरत और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को देश के दूसरे और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर बनने पर सम्मानित किया। वहीं केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों की श्रेणी में यूपी के वाराणसी को पहला स्थान मिला है। जबकि महापौर संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में कड़े कॉम्पाइटिशन के बावजूद 269 से 12वें नंबर पर लखनऊ रहा। मेरयर संयुक्ता भाटिया की माने तो यूपी का सबसे साफ शहर लखनऊ बना है।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देश के 342 साफ शहरों को सम्मानित किया। इन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए कुछ स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय आवास उत्तर प्रदेश में कानपुर चौथे नंबर पर था।



एक साल में कई काम हुए

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई निजी शौचालय बनवाए गए।
- गंगा खुले में शौच से फ्री हुए।
- कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट बने।
- दिन के अलावा रात के शिफ्ट में भी सफाई शुरू करवाई गई।
- कूड़ाधार मैकेनाइज किए गए।
- अवैध डिपिंग जोन हटाए गए।
- कॉम्पैक्टर लगाए गए। इससे सड़कों पर कूड़ा नहीं फैलता।
- डोर टु डोर कूड़ा कलेक्शन का दायरा बढ़ाया गया।

एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा-मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में भी पुरस्कृत किया गया है। वहीं लखनऊ देश में 12वें और प्रदेश में पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद दूसरे और कानपुर तीसरे नंबर पर है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में कानपुर चौथे नंबर पर था।

नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी का कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। इसी का नतीजा है कि रैंकिंग सुधारी है। 2016 में मिलियन प्लस शहरों की कैटिगरी में 28वें नंबर पर रहने वाला लखनऊ 2017 में 51वें नंबर पर पहुंच गया था। 434 शहरों की लिस्ट में लखनऊ देश में 269वें और यूपी में 10वें नंबर पर था।

बीमा कंपनियों को हर कीमत पर देना होगा मोटर दुर्घटना मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जिसकी मृत्यु के समय कार्ड आय नहीं थी, उनके कानूनी उत्तराधिकारी भी भविष्य में आय में वृद्धि को जोड़कर भविष्य की संभावनाओं के हकदार होंगे। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस बात की उम्मीद नहीं है कि मृतक अगर किसी भी सेवा में नहीं था या उसकी नियमित आय रहने की संभावना नहीं है या फिर उसकी आय स्थिर रहेगी या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के सामने आए इस मामले में 12 सितंबर 2012 को हुई दुर्घटना में बीई (इंजीनियरिंग) के तीसरे वर्ष में पढ़ रहे 21 वर्ष छात्र की मौत हो गई, वह दावेदार का बेटा था। हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को 12,85,000 रुपए से घटाकर 6,10,000 रुपये कर दिया है। ट्रिव्यूनल द्वारा दिए गए 15,000 रुपए प्रति माह की बजाय मृतक की आय का आकलन 5,000 रुपए प्रति माह



किया। अपील में कहा गया कि मजदूरों/कुशल मजदूरों को भी 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत पांच रुपए प्रति माह मिल रहे थे। कोर्ट ने कहा, शैक्षिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और जैसा कि ऊपर देखा गया है, मृतक सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, हमारी राय है कि मृतक की आय कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए कि साल 2012 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी

यूनियन ऑफ इंडिया का तर्क खारिज

यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया कि मृतक नौकरी नहीं कर रहा था और हादसे के समय भविष्य में आय की संभावना/भविष्य की आय में वृद्धि के लिए और कुछ नहीं जोड़ा जाना है। नेशनल इंशेयरेस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य का जिक्रकरते हुए कोर्ट ने कहा, हम कोई कारण नहीं देखते हैं कि उक्त सिद्धांत को क्यों लागू नहीं किया जा सकता है, जो वेतनभोगी व्यक्ति या मृतक एक निश्चित वेतनभोगी मृतक पर लागू होता है, जो मृतक के लिए सेवा नहीं कर रहा था या उसके पास दुर्घटना के समय कोई आय नहीं था।

मजदूरों/कुशल मजदूरों को पांच हजार रुपये प्रति माह मिल रहे थे।

योगी के मंत्री बोले- मुख्तार अंसारी का राजनीतिक शूटर है ओम प्रकाश राजभर

» अनिल राजभर ने कहा- शूट करके भेज दूंगा घर

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे राजनीतिक शूटरों को शूट करने की जिम्मेदारी हमको दे रखी है। 2022 में इन लोगों को हम शूट करके घर भेज देंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया दिया जाय। जिनका न कोई आगे न कोई सिद्धांत है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले पर कहा कि हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हृदय है।

अनिल राजभर ने आगामी चुनाव में हार के डर से कृषि कानून लिए जाने पर कहा कि ये लोग माफिया मुख्तार अंसारी के राजनीतिक शूटर बन गए हैं। हमारे

सीएम योगी को दी जान से मारने की धमकी, गिरफ्तार

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

धनबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अराजक तत्वों के निशाने पर हैं। कई बार सोशल मीडिया के जरिये उन्हें धमकी दिए जाने की खबरें भी सामने आती रही हैं। इसी क्रम में धनबाद से कुछ ही दूरी पर परिचम बंगल के रानीगंज से मोहम्मद नौशाद नाम के

युवक की गिरफ्तारी की गई है। जानकारी के अनुसार इस आरोपी को यूपी पुलिस अपने साथ लेकर लखनऊ चली गई है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने रानीगंज से टिकटर पर योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द कहे थे और धमकी दी थी।

30 नवंबर से पहले आरएलडी-सपा का गठबंधन !

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल (रालोद-सपा) के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर बढ़ा बायान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस महीने यानी नवंबर के अंत तक सपा के साथ गठबंधन को लेकर फैसला ले लिया जाएगा।

जयंत ने कहा कि अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, मिलते रहे हैं और साथ भी चले रहे हैं। सारी चीजों पर लगातार बात होती रहेगी। औपचारिक घोषणा कुछ



» आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने कहा- इसी महीने के अंत तक हम आ जाएंगे साथ

दिनों में हो जाएंगी। वहाँ समाजवादी के साथ गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बारे में पूछे जाने पर जाट नेता ने कहा कि घोषणा तो हम साथ बैठकर करेंगे,

इस महीने के आखिर तक हम फैसला ले लेंगे। वहीं कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद जाटलैंड के नाम से मशहूर और चौधरी खानदान की कर्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन की किसी संभावना को लेकर सवाल किए जाने पर जयंत चौधरी ने कहा, बीजेपी का दामन थामने का आधार क्या होगा? उत्तर प्रदेश में लोग तंग हैं। योगीजी को गवर्नर्स का पता ही नहीं है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बड़े-बड़े बादे तो करते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है उस पर कुछ नहीं करते हैं।